जनसत्ता

हिंसा की सियासत

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर हिंसा को लेकर राजनीति गरमा गई है। विजयादशमी वाले दिन मुर्शिदाबाद में एक शिक्षक के घर में घुस कर अज्ञात लोगों ने शिक्षक सहित उसकी गर्भवती पत्नी और एक छोटे बच्चे की हत्या कर दी। उसके बाद शनिवार को नदिया जिले में एक दुकानदार की उसकी पत्नी के सामने गोली मार कर हत्या कर दी गई। ये सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। इसे लेकर प्रांतीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये हत्याएं राजनीतिक हैं और इनके पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ है। जबकि तृणमूल कांग्रेस इस आरोप को खारिज कर रही है। इस तरह एक बार फिर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भाजपा के निशाने पर है। सवाल है कि विजयादशमी के दिन से लेकर अब तक पुलिस मुर्शिदाबाद हत्याकांड में ठीक से जांच भी शुरू क्यों नहीं कर पाई है। इस पर राज्यपाल को दखल देना पड़ा है। हत्या की वजहें जो भी हों, पर उसमें अगर प्रशासन ढुलमुल रवैया बनाए रखे तो सरकार पर अंगुलियां उठनी स्वाभाविक हैं।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का सिलसिला नया नहीं है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या चुनाव की प्रक्रिया चल रही होती है, तो वहां हिंसक घटनाओं का सिलसिला बढ़ जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर अभी सरकार निशाने से बाहर नहीं आ पाई है कि हाल की घटनाओं ने उसे फिर से निशाने पर ला खड़ा किया है। वहां विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, और बताया जा रहा है कि इसी कारण सियासी वैमनस्यता सिर उठाने लगी है। छिपी बात नहीं है कि वहां जो भी पार्टी सत्ता में रहती आई है, उसके और मुख्य प्रतिद्वंद्वी दल के कार्यकर्ता के साथ हिंसक झड़पें होती रही हैं। पहले ऐसी घटनाएं माकपा, कांग्रेस या फिर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुआ करती थीं, अब ममता बनर्जी सरकार के आने के बाद तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच देखी जाने लगी हैं। जब भी ऐसी कोई हिंसक घटना होती है, दोनों में से कोई न कोई पार्टी पीड़ित पक्ष को अपना कार्यकर्ता बता कर दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देती है।

विचित्र है कि इसमें पुलिस की भूमिका पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के पीछे वजहें छिपी नहीं हैं। अक्सर कई लोग अपने कारोबारी या फिर दूसरे निजी हित साधने के मकसद से सत्ताधारी दल से नजदीकी बना लेते हैं। इस तरह उन्हें प्रशासनिक संरक्षण भी प्राप्त हो जाता है। जिस तरह ममता बनर्जी खुद अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए पुलिस थाने में पहुंच जाती रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह उनकी पार्टी के कार्यकर्ता महफूज महसूस करते होंगे। इसलिए आपराधिक घटनाओं पर काबू पाने के मामले में स्वाभाविक ही ममता बनर्जी सरकार पर अंगुलियां उठती रही हैं। संभव है, विपक्षी दलों के कुछ आरोप गलत हों, पर अगर ममता बनर्जी की सरकार आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर सचमुच संजीदा होती, तो इस तरह हिंसक घटनाओं का सिलसिला न चलता रहता और न विरोध प्रदर्शनों की नौबत आती। कोई भी सरकार जब तक अपने दलगत स्वार्थों से ऊपर उठ कर राज्य में कानून-व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होती, तब तक आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना मुश्किल ही बना रहता है।

मंदी की मार

भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की मार से किस तरह कराह रही है, इसका पता उद्योग जगत की बिगड़ती दशा से चलता है। एक बार फिर यह निराशाजनक तस्वीर सामने आई है कि अगस्त में औद्योगिक उत्पादन 1.1 फीसद और गिर गया और पिछले इक्यासी महीनों में यह सबसे कम स्तर पर आ गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बता रहा है कि कारखानों में उत्पादन काफी नीचे चला गया है और निर्माण क्षेत्र की गतिविधियां भी मंद पड़ी हुई हैं, रीयल एस्टेट में खरीदारी पर ग्रहण लगा है। यह चिंताजनक स्थिति है और हालात को काबू करने के लिए सरकार के सारे उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं। त्योहारी महीने में अगर आर्थिक सुस्ती का ये आलम देखने-सुनने को मिले तो लोग खुश कैसे होंगे, यह सोचने वाली बात है। ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि मंदी का यह माहौल आने वाले महीनों में और हालत खराब करेगा। अगले छह-आठ महीनों में भी इस बात के आसार नहीं हैं कि कहीं से कोई सुधार या तेजी के संकेत मिलने लगें।

मंदी के संकेत साल भर पहले से मिलने लगे थे। सबसे पहले और ज्यादा असर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गिरावट से दिखना शुरू हो गया था। पिछले दस महीने से वाहन निर्माता कंपनियों का उत्पादन और बिक्री का ग्राफ नीचे जा रहा है। गाड़ियां बिक नहीं रहीं, इसलिए कंपनियों ने पहला कदम उत्पादन में कटौती का उठाया, इसके बाद कामगारों की छंटनी का दौर चला। लेकिन सरकार तब इसे अल्पकालिक संकट मानते हुए नजरअंदाज करती रही। उसके परिणाम आज सामने हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र- विनिर्माण, ऊर्जा, खनन, इस्पात सब संकट में हैं। यह लगातार तीसरा महीना है जब उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों का उत्पादन गिरता गया है। निर्माण क्षेत्र में 2014 के बाद सबसे कम वृद्धि का आंकड़ा है। खनन क्षेत्र में उत्पादन पिछले आठ महीने में अपने न्यूनतम स्तर पर है। जाहिर है, बाजार में मांग नहीं है। बेरोजगारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है और मंदी के कारण लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उस सूरत में पैसा आएगा कहां से खर्च करने के लिए, यह बड़ा सवाल है। जिनके पास थोड़ा-बहुत पैसा है भी, वे आर्थिक संकट को देखते हुए उसे भविष्य के लिए बचा कर रखे हुए हैं, खर्च करने से डर रहे हैं। इसलिए बाजार में नगदी का संकट बन गया है।

रिजर्व बैंक पहले ही कह चुका है कि वह जरूरत को देखते हुए नीतिगत दरों में और कटौती कर सकता है। केंद्रीय बैंक इस साल पांच बार नीतिगत दरों में बदलाव कर चुका है, जो पिछले नौ साल के न्यूनतम स्तर पर जा चुकी है। इस कवायद का सारा जोर बाजार में मांग पैदा करना है, ताकि लोग खरीदारी के लिए पैसा निकालें। हाल में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच फीसद बढ़ाने के पीछे भी यही बड़ी वजह रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या केंद्रीय बैंक के पास नीतिगत दरों में कटौती के अलावा कोई और चारा नहीं रह गया है। इस वक्त अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को लेकर लोगों के मन में जो डर पैदा हो गया है, उसे निकालने की जरूरत है। बैंक भी कर्ज देने में डरे हुए हैं, इसलिए तमाम कोशिशों के बावजूद कर्ज लेने वालों का आंकड़ा बढ़ नहीं रहा। सरकार ने कारपोरेट करों में कटौती जैसे कदम तो उठाए हैं, लेकिन उससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? जरूरत है मध्यमवर्ग की आमद बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं, उस पर से करों का बोझ हल्का किया जाए, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए।

कल्पमेधा

गलतफहमियों में डूबे रहना, गलतियां करने से भी ज्यादा खतरनाक है।
-बर्नार्ड शॉ

सोने की बढ़ती चमक

जयंतीलाल भंडारी

दुनिया के केंद्रीय बैंक डॉलर की तुलना में सोने को महत्त्व दे रहे हैं और सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे एक वजह अमेरिकी डॉलर की धमक कम करना भी है। रूस, चीन और भारत सहित दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने पिछले कुछ महीनों में काफी मात्रा में सोना खरीदा है। छह सौ तेरह टन के सोने के भंडार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक इस मामले में दसवां सबसे बड़ा सोने के भंडार वाला केंद्रीय बैंक है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता देश है और अपनी लगभग पूरी स्वर्ण मांग आयात के जरिए पूरी करता है। ऐसे में सोने के आयात में कमी अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है। आर्थिक सुस्ती के वर्तमान दौर में सोने के आयात में कमी से व्यापार घाटे में भी कमी आएगी। निश्चित रूप से भारत जैसे विकासशील देश के लिए सोने में निवेश उत्पादक नहीं है। प्रतिवर्ष देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब तीन फीसद सोने की खरीद के रूप में अनुत्पादक पूंजी में बदल रहा है।

यकीनन वर्ष 2019 की शुरुआत से ही देश में सोने का आयात कम होने का परिदृश्य दिखाई दे रहा है। आमतौर पर देश में दीवाली जैसे त्योहार की तैयारी के मौसम में सोने की मांग तेजी से बढ़ती है और भारत का स्वर्ण आयात बढ़ जाता है। लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यदि हम आंकड़ों की तरफ देखें तो पाते हैं कि सोने का आयात तीन वर्ष के निचले स्तर पर आ गया है। पिछले महीने भारत ने छब्बीस टन सोने का आयात किया था, जो एक साल पहले के 81.71 टन से कम है। ऐसे में चालू महीने यानी अक्तूबर में सोने की मांग में कितनी भी वृद्धि हो जाए, इसका आयात पचास टन से कम रहने के आसार हैं।

इस समय देश और दुनिया में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। बड़े निवेशक सोने में निवेश करके भारी लाभ कमा रहे हैं। हालांकि देश और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में नरमी और गिरावट का दौर चल रहा है। प्रॉपर्टी बाजार ठंडा पड़ा है। शेयर बाजार भी कभी उतरते हुए तो कभी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोना उन गिनी-चुनी परिसंपत्तियों में है जो छोटे-बड़े सभी निवेशकों के लिए सुरक्षित और आकर्षक लग रहा है। विशेषज्ञ यह स्वीकार करते हैं कि शेयर, रीयल एस्टेट और सोना लंबी अवधि में सबसे अधिक प्रतिफल देने वाली परिसंपत्तियां होती हैं। इसलिए विशेषज्ञ पिछले कुछ वर्षों के दौरान सोने का प्रदर्शन कमजोर रहने के बावजूद निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में इस पीली धातु की हिस्सेदारी बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं।

भारत में निवेश के चार बड़े साधन माने जाते रहे हैं। सोना, संपत्ति, शेयर और बचत योजनाएं। बीते वर्षों में विशेष रूप से वर्ष 2013 के बाद सोने की चमक फीकी पड़ी है। उस समय सरकार ने शुल्क बढ़ा कर और आयात पर अंकुश लगा कर खरीदारी को हतोत्साहित किया था, जिससे सोना अपने सबसे ऊंचे स्तर से लुढ़कने लगा था। उस अवधि में शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। रीयल एस्टेट भी एक अन्य महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति वर्ग है, लेकिन यह बहुत से नियमों, करों और परिसंपत्ति को बेचना आसान नहीं होने के कारण कमजोर बना हुआ है। इसके अलावा रीयल एस्टेट के लंबी अवधि के प्रतिफल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और न ही यह प्रतिफल पूरे देश में एकसमान है। करीब चार दशक से सूचकांक के आंकड़े उपलब्ध हैं और इस दौरान शेयरों ने अच्छा प्रतिफल दिया है। पिछले एक दशक में सोने का प्रतिफल शेयरों से अधिक रहा है। ऐसा लगता है कि भारत में सोना अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने और हाल में निवेश पोर्टफोलियो में सोने का हिस्सा बढ़ाने की चर्चाओं से परिदृश्य बदल रहा है। इस पीली धातु में अन्य संपत्ति वर्गों की तुलना में कई खूबियां हैं। सोने में अन्य वित्तीय बाजारों, विशेष रूप से शेयरों की तुलना में अलग रुझान होता है। निवेशकों को सोना खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कारक भी अलग होते हैं। भारत में सोना परिवारों की जरूरत है और सोने के आभूषण पहनना भारतीय संस्कृति का अंग भी है। लोग धार्मिक आस्था की वजह से मंदिरों में सोना चढ़ाते हैं।

यदि हम देश में सोने की बढ़ती हुई कीमतों और सोने में निवेश करने वाले निवेशकों का ग्राफ देखें, तो पाते हैं कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 के पहले पांच महीनों यानी अप्रैल से सितंबर के बीच देश में सोना निवेशकों को बाईस प्रतिशत से अधिक का लाभ दे चुका है। जबकि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष 2018-19 में सोने के निवेशकों को लगभग दस प्रतिशत का लाभ मिला था। इस महीने में अब तक देश में सोने की कीमतें छह साल की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। अर्थविशेषज्ञों का कहना है कि

इस साल के अंत तक सोना बयालीस हजार प्रति दस ग्राम तक पहुंच सकता है।

इस समय दुनिया में सोने की कीमतें बढ़ने के कई कारण दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के केंद्रीय बैंक डॉलर की तुलना में सोने को महत्त्व दे रहे हैं और वे सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे एक वजह अमेरिका और डॉलर की धमक कम करना भी है। रूस, चीन और भारत सहित दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने पिछले कुछ महीनों में काफी मात्रा में सोना खरीदा है। छह सौ तेरह टन के सोने के भंडार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) इस मामले में दसवां सबसे बड़ा सोने के भंडार वाला केंद्रीय बैंक है। सोने की कीमतों में नई तेजी की जड़ें दुनिया के कई विकसित देशों द्वारा डॉलर के नए विकल्प की तलाश में नीहित हैं।

दुनिया में सोने की कीमत बढ़ने का दूसरा बड़ा कारण अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध भी है। इससे वैश्विक मंदी का माहौल बन गया है। ऐसे में निवेशक सोने की खरीदी को उपयुक्त मान रहे हैं। अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावना से भी डॉलर कमजोर हुआ है और इससे सोने की चमक तेज हुई है। चीनी मुद्रा के अवमूल्यन से मुद्रा बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने भी सोने के दाम बढ़ाए हैं। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी पर आतंकी हमले के साथ खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव से भी सोना महंगा हुआ है। अमेरिका ने यूरोप के सामान पर शुल्क बढ़ाने का जो रदम उठाया, उससे भी सोने की चमक और बढ़ी। भारत में सोने की कीमत बढ़ने के दो अन्य कारण भी हैं। इनमें एक कारण इस साल के बजट में सोने पर सीमा शुल्क दस फीसद से बढ़ा कर साढ़े बारह फीसद कर दिया जाना है और दूसरा कारण मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर हुआ है।

हालांकि भारत में सोने के दाम अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन नए सोने की मांग अधिक नहीं बढ़ी है। लोग भी सोना बेच कर मुनाफा बनाने में लगे हैं। सरकार को चाहिए कि सोने की खरीदारी के इच्छुक निवेशकों को सोने की खरीदी की तुलना में स्वर्ण बांड के विकल्प की ओर प्रवृत्त करने की कोशिश करे। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों के अलावा सॉवरेन गोल्ड बांड भी आ गए हैं और ये स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं। इन दो विकल्पों ने पहले ही भौतिक रूप में सोना खरीदने की जरूरत खत्म कर दी है और इस पीली धातु को सही मायनों में ऐसा निवेश उत्पाद बना दिया है, जिसमें भौतिक सोने के साथ पैदा होने वाला भावनात्मक जुड़ाव आड़े नहीं आता है। स्वर्ण बांड में निवेश पर सरकार ने कई तरह की रियायतों की घोषणा की है, जिससे इसमें निवेश ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके तहत एक ग्राम सोने के मूल्य के बराबर न्यूनतम बांड में निवेश कर सकते हैं। स्वर्ण बांड की बिक्री पर होने वाले लाभ पर किसी तरह का कर नहीं लगता है। ऐसा किया जाना सोने के निवेशकों के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभप्रद होगा।

झूठ का परदा

मोनिका अग्रवाल

दुनिया मेरे आगे

आज जीवन-शैली कुछ ऐसी हो गई है कि अधिकतर लोगों को झूठ बोलने में कोई हिचक नहीं होती। बहुत से लोगों का तर्क तो यह भी होता है कि किसी के भले के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं होता। यह तर्क और इसका खेल यहां पर भी नहीं रुकता। धोखा तो किसी को भी देना बुरी बात है, किसी के भरोसे को तोड़ना है और कानूनी संदर्भ आने पर दंडनीय अपराध है। लेकिन खुद को धोखा देना तो आत्मघात के समान है। अपने जीवन और भविष्य के साथ खतरनाक खिलवाड़ है। जब कोई बढ़-चढ़ कर अपनी बड़ाई करता है या झूठ बोलता है, तो कई बार वह एक तरह से खुद को धोखा दे रहा होता है।

अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना होता है, जब लगता है कि बच्चा हो या बड़ा, ज्यादातर लोगों की रग-रग में झूठ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बस गया है। झूठ बोलने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। कुछ लोग तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। बिना किसी फायदे या नुकसान के, बिना किसी का भला या बुरा सोचे, बेबाक झूठ बोल दिया जाता है। जो बात झूठ से शुरू हो तो क्या वह सच पर खत्म होगी? मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा! झूठ पर झूठ का एक सिलसिला चालू हो जाता है। ऐसे लोग हर पल अपनी बात बदलते रहते हैं और उनके झूठ से सबसे ज्यादा परिवार के सदस्य और उनके सगे-संबंधी ही परेशान होते हैं। वे ज्यादा परेशान इसलिए होते हैं कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति आमतौर पर खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश करता रहता है। वह अपने झूठ को छिपाने के लिए हर हाल में अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करता है। अगर हम ऐसे व्यक्ति को सही-गलत सिखाना या बताना चाहते हैं तो वह उलट कर हमें ही दोषी करार देने लगता है। उसे न प्यार की भाषा समझ में आती है, न डांट की।

मनोविश्लेषकों का कहना कि इस तरह के लोग दूसरों को प्रभावित करने के आशय से अपने और अपने काम, अपनी उपलब्धियों के बारे में इस प्रकार झूठी बातें बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं कि बाद में वे खुद ही उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं। उनका मन-मस्तिष्क उनकी ऐसी गप्प को भी सही मान बैठता है। परिणाम यह होता है कि इसी भुलावे में वे अपने कार्य निष्पादन, कर्तव्य, दायित्व के प्रति लापरवाह और आखिरकार उदासीन हो जाते हैं और इस तरह परेशानी में पड़ जाते हैं। एक कहावत है कि 'एक झूठ को छिपाने के लिए सौ झूठ बोलने पड़ते हैं!' अपनी अस्तित्वहीन उपलब्धियों, सफलताओं का ढिंढोरा पीटने वाले ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि भेद एक दिन तो खुलना ही है। वास्तविकता सामने आने पर बेवजह शर्मिंदा होने के कारण ऐसे लोग तरह-तरह के बहाने बनाने लगते हैं, दलीलें पेश करते हैं। फिर दूसरों के मत्थे दोष मढ़ने का भी प्रयास करते हैं और इस प्रकार पतन के फिसलन भरे रास्ते पर तेजी से चल पड़ते हैं।

इसलिए अपने प्रति ईमानदार होना अनिवार्य है। अपनी कमियों, कमजोरियों, त्रुटियों को जानना, पहचाना, मानना नितांत जरूरी है। तभी उन्हें सुधारने का प्रयास हो पाएगा। इलाज से पहले रोग का निदान आवश्यक होता है। अपनी कमियों को खुद से छिपा कर, उन पर परदा डाल कर, उन्हें नकार कर हम केवल उस कबूतर की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं जो बिल्ली को देख कर करता है। जब बिल्ली उसके नजदीक आती है, तब वह यह मान कर आंखें मूंद लेता है कि बिल्ली भी उसे नहीं देख रही है। इसी भुलावे में वह आखिर जान से हाथ धो बैठता है। कमी और कमजोरी किसमें नहीं होती! कमियां और कमजोरी होना बुरा नहीं है। बुरा है उसे स्वीकार करके सुधारने की बजाय उस पर परदा डालना। दूसरों द्वारा दिए गए धोखे से तो इंसान निपट भी लेता है, पर अपने आपसे धोखा करके भला कहां रह सकता है? इसी व्याधि का एक अन्य रूप यह भी है कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति का मान-सम्मान धीरे-धीरे नष्ट होने लगता है।

झूठ का एक पहलू यह भी है कि जब हम किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं और जब तक हमें इस बात का एहसास होता है, तो उस एहसास के होने से पहले ही दूसरा व्यक्ति हम पर भरोसा करना छोड़ चुका होता है। हम आत्मसमर्पण भी कर लें तो वह भरोसा पूरी तरह वापस नहीं आता। इसलिए कुछ आकांक्षा रखना बुरा नहीं है। लेकिन झूठ-मूठ का दिखावा करना, दूसरों को नहीं, अपने आप को धोखा देना है। ऐसा झूठ, ऐसी दोहरी जिंदगी कितनी देर चल सकती है? देर-सवेर कलई खुल ही जाती है। अंदाजा लगाइए कि सबसे सामने पोल खुलने के बाद कितनी शर्मिंदगी और कैसी हास्यास्पद स्थिति होती होगी!

चीन का स्वार्थ

चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पूर्व चीन की ओर से बयान आया था कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी मसला है जिसे दोनों देशों को परस्पर शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कश्मीर पर चीन का अचानक पलटना एक तरफ भारतीय पक्ष को मजबूत करता है, तो चीन के इतिहास को देखते हुए हमें निरंतर सजग रहने की जरूरत भी रेखांकित करता है। पहले भी पंचशील समझौता करके चीन भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण कर हमारी संप्रभुता को चुनौती देने का दुस्साहस कर चुका है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद चीन लगातर पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आया है। उसने संयुक्त राष्ट्र से भी कश्मीर मुद्दे पर संज्ञान लेने की मांग की थी। लेकिन अब इसे द्विपक्षीय मुद्दा बता कर उसने पलटी मारी है तो इसके पीछे उसके अपने स्वार्थ हैं। वह अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध, हांगकांग में विरोध, उईगर में मुसलमानों के उत्पीड़न के कारण खराब होती छवि जैसी मुश्किलों में फंसा है।

इन संकटों से निकलने के लिए वह अपनी छवि को अच्छा बनाने के लिए ही निष्पक्ष होने का दिखावा कर रहा है। भारत चीन के बीच व्यापार आज लगभग सौ अरब डालर सालाना तक पहुंच चुका है। लगभग एक हजार चीनी कंपनियों ने अरबों डालर का निवेश भारत में किया हुआ है। बढ़ते व्यापार और भारतीय बाजार की अनदेखी करना आज चीन तो क्या किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। चीन के बदलते हुए रुख की एक वजह यह भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है।

● *बिजेंद्र कुमार, आंबेडकर कालेज, दिल्ली*

सकारात्मक पहल

यह प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली की लगभग पांच सौ दुर्गा पूजा समितियों ने दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन इस बार कृत्रिम तालाबों में किया और पर्यावरण की रक्षा में अपना अमूल्य योगदान दिया। ये कामचलाऊ तालाब दिल्ली सरकार ने बनवाए थे, ताकि यमुना को प्रदूषण से बचाया जा सके। बड़ी बात यह है कि लोग अब पर्यावरण रक्षा की आवश्यकता, उसके महत्त्व और उसके प्रति अपने दायित्व को समझ रहे हैं। कृत्रिम तालाबों नहीं होने से लोग यमुना में मूर्ति विसर्जन करते थे और इससे घाटों पर गंदगी फैलती थी और नदी भी प्रदूषित हो जाती थी। निसंदेह इस सकारात्मक पहल के लिए दिल्ली सरकार प्रशंसा की पात्र है।

इसके पहले भी छठ के अवसर पर इस दिल्ली सरकार ने कालोनियों के आसपास इसी प्रकार के छोटे-छोटे कृत्रिम तालाबों का प्रबंध करके लोगों को यमुना में जाने की कठिनाई से बचाने की पहल की थी। इसका लाभ यह हुआ था कि यमुना के घाटों की स्वच्छता और सुंदरता की भी रक्षा हुई, क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां जाते और पूजा सामग्रियों के अवशिष्ट और प्लास्टिक की थालियां घाटों पर फेंक देते थे। इस प्रकार के सहयोग को देखते हुए यह विश्वास करना कठिन नहीं है कि पर्यावरण को ध्यान में रख कर ही लोग दीपावली में उच्चतम न्यायलय द्वारा सुझाए गए हरित पटाखे ही छोड़ेंगे। इससे दिसंबर-जनवरी हर साल छाने वाली धुंध भी कम पड़ेगी। पर्यावरण को बचाने की रोई भी पहल बिना जनभागीदारी के संभव नहीं हो सकती। अगर हमें वातावरण को बचाना है और हवा को साफ रखना है तो अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी।

● *राजेंद्र प्रसाद सिंह, दिल्ली*

कैसे मिले रोजगार

देश में आज बेरोजगारी बड़ी समस्या के रूप में मौजूद है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआइई) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर सात फीसद है और पिछले दो वर्षों से बेरोजगारी दर में इजाफा तेजी से हुआ हैं। बेरोजगारी दूर करने में सरकारें असफल साबित हुई हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खाली पड़े पदों को भरने में उदासीन रवैया अख्तियार कर रही हैं। दूसरी ओर निजी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर होने के बावजूद उद्यमियों को अपेक्षित कौशल और जरूरत के अनुसार उम्मीदवार नहीं मिल पाने की शिकायत है। अशिक्षित लोगों के मुकाबले शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की दर ज्यादा हैं, क्योंकि शिक्षित लोग अपनी योग्यता और डिग्री के अनुरूप रोजगार के तलाश में होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शिक्षित व्यक्ति की डिग्री का ज्ञान और पाठ्यक्रम रोजगार हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए देश में रोजगारोन्मुख शिक्षा व्यवस्था को लागू करना जरूरी है। इसके लिए शिक्षा पाठ्यक्रम और व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, कोंढाली (नागपुर)*

बराबरी का दर्जा

महिलाओं को सिर्फ आलेखों में और तकरीरों में बराबरी का दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिला कर देश दुनिया के विकास में लगी हैं। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, महिलाओं को बराबरी का हक कहीं नहीं मिला है। चाहे शिक्षण संस्थान हों या वेतन में समानता की बात हो, आज भी पूरे विश्व में स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए पुरुष प्रधान समाज से संघर्ष करना पड़ रहा है। कहते हैं कि चार दशक के बाद ईरान की महिलाओं को स्टेडियम में जाकर फुटबाल मैच देखने की इजाजत मिली। एक और रूढ़ि से जकड़े देश सउदी अरब ने भी कुछ उदारता बरती है। सउदी अरब में पहले महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत मिली, फिर उन्हें अकेले विदेश यात्रा पर जाने की छूट दी गई। उसके बाद अब सैन्य सेवा में भी महिलाओं की भर्ती को हरी झंडी दे दी गई। देर से ही सही, ईरान और सऊदी अरब की देखा-देखी अन्य देश भी महिलाओं को समानता का अधिकार देने को बाध्य होंगे।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी (जमशेदपुर)*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com